



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ३८ (४)]

मंगळवार, डिसेंबर ८, २०१५/अग्रहायण १७, शके १९३७

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

### असाधारण क्रमांक ६६

#### प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

#### महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ८ दिसंबर, २०१५ ई.को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

#### L. A. BILL No. LI OF 2015.

##### A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL  
PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT,  
1963.

विधानसभा का विधेयक क्र. ५१ सन् २०१५।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में  
अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् २०१५ **क्योंकि**, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन)  
का महा. अध्यादेश, २०१५, १६ जून २०१५ को प्रख्यापित किया था ;  
अध्या. क्र. १४।

**और क्योंकि,** १३ जुलाई २०१५ को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, २०१५ (सन् २०१५ का विधान सभा विधेयक क्र. २८), १४ जुलाई २०१५ को महाराष्ट्र विधान सभा द्वारा पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को प्रेषित किया गया था ;

**और क्योंकि,** तत्पश्चात्, ३१ जुलाई २०१५ को महाराष्ट्र विधान परिषद का सत्रावसान हो जाने के कारण, उक्त विधेयक महाराष्ट्र विधान परिषद द्वारा पारित नहीं किया जा सका था ;

**और क्योंकि,** भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान के पश्चात्, अर्थात् २३ अगस्त २०१५ के बाद प्रवृत्त होने से परिविरत हो जाएगा ;

**और क्योंकि,** राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) अध्यादेश, २०१५, २१ अगस्त २०१५ को प्रख्यापित किया गया था ;

**और क्योंकि,** उक्त अध्यादेश को विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिये, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन तथा जारी रहना) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह १६ जून २०१५ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १३ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (जिसे इसमें आगे “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा १३, की उप-धारा (१ख) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

सन् १९६४ का महा. २० ।

“(१ग) (क) राज्य सरकार, **राजपत्र** में किसी आदेश द्वारा,—

(एक) चार विशेष निमंत्रित, प्रत्येक बाजार समिति पर जिसकी आय धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत फीस से सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड़, रुपयों से अधिक है ; और

(दो) दो विशेष निमंत्रित, प्रत्येक बाजार समिति पर जिसकी आय धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत फीस से सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड़ रुपयों तक है, जो कृषि, कृषक प्रसंस्करण, कृषि विपणन, विधि, वित्त या वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे, को नियुक्त कर सकेगी।

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त विशेष निमंत्रितियों को, बाजार समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा परंतु, उसकी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(ग) विशेष निमंत्रितियों की पदावधि, बाजार समिति के सदस्यों की पदावधि के साथ ही सह-पर्यवसित होगी।”।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १६ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१५, एतद्वारा, निरसित, किया जाता है।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १६ ।

(२) ऐसे निरसित के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन कृत किसी बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी के उपबंधों अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

### उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०), बाजार क्षेत्रों में, कृषक और कृषिपय अन्य उपज के विपणन और राज्य में इसलिये स्थापित निजी बाजारों और किसान ग्राहक बाजारों समेत बाजारों के विकास और विनियमन के लिये ; ऐसे बाजारों के संबंध में गठित या संबंधित प्रयोजनों के लिये कार्य कर रही बाजार समितियों को शक्ति प्रदान करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

२. उक्त अधिनियम के अधीन गठित बाजार समितियों के प्रभावी और सुचारू कार्य करने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र सरकार, बाजार समितियों पर विशेष निर्मात्रितियों के रूप में कृषि, कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन, विधि, वित्त और वाणिज्य क्षेत्रों में से विशेषज्ञों की नियुक्ति करना इष्टकर समझती थी, ताकि बाजार समिति को, ऐसे विशेषज्ञों के ज्ञान द्वारा लाभ होगा। यह भी उपबंध करने के लिये प्रस्तावित किया गया था कि ऐसे विशेष निर्मात्रितियों को समिति की चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु, मत देने का अधिकार नहीं होगा। उस प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की धारा १३ में एक नयी उप-धारा (१ग) की निविष्टि करने का प्रस्तावित किया गया था।

३. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र कृषि, उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ (सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १४) १६ जून २०१५ को प्रख्यापित किया गया था।

४. तत्पश्चात्, १३ जुलाई २०१५ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलने के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, २०१५ (सन् २०१५ का विधान सभा विधेयक क्र. २८), १४ जुलाई २०१५ को महाराष्ट्र विधान सभा में पारित किया गया था और महाराष्ट्र विधान परिषद को पारेषित किया गया था। तथापि, तत्पश्चात्, ३१ जुलाई २०१५ को राज्य विधान मंडल का सत्रावसान हो जाने के कारण, उक्त विधेयक विधान परिषद में पारित नहीं किया जा सका था।

५. भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के उपबंधों के प्रवर्तन द्वारा, उक्त अध्यादेश, २३ अगस्त २०१५ के पश्चात्, जिस दिनांक को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान पर अर्थात् २३ अगस्त २०१५ के बाद प्रवर्तित होने से परिवर्तित हो जायेगा। और महाराष्ट्र सरकार, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझती थी। और, इसलिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१५ (सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १६) २१ अगस्त २०१५ को महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

६. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

चंद्रकांत (दादा) पाटील,

विपणन मंत्री।

मुंबई,

दिनांकित ४ नवम्बर, २०१५ ।

**प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन**

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्न प्रस्ताव अन्तर्गस्त है, अर्थात् :—

**खण्ड २.**— इस खण्ड के अधीन, जिसका आशय महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३, की धारा १३ की उप-धारा (१ग) को निविष्ट करने के लिए प्रस्तावित है, जिसमें प्रत्येक बाजार समिति पर, जिसकी आय धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत फीस से सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड रुपयों से अधिक है, चार विशेष निमंत्रित ; और प्रत्येक बाजार समिति पर जिसकी आय, सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड रुपयों तक है, दो विशेष निमंत्रित जो कृषि, कृषक प्रसंस्करण, कृषि विपणन, विधि, आर्थिक या वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे, की नियुक्ति करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ उपर्युक्त प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।

(यथार्थ अनुवाद),

**डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,**

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन :

नागपूर,

दिनांकित ८ दिसंबर, २०१५।

**डॉ. अनंत कळसे,**

प्रधान सचिव,

महाराष्ट्र विधानसभा।